

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - डिक्री 14 सन् 2014

पंजीयन दिनांक 10.03.2014

भेरूलाल पिता हीरा जाट निवासी बोदियाना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

विरुद्ध

1. सोहनी पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी बोदियाना हाल मुकाम सोपुरा तहसील गंगार जिला चित्तौड़गढ़
2. उप-पंजीयक उप-पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्टगण



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 60/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2014

- उपस्थित-
1. गौरव परमार -अधिवक्ता अपीलान्ट
 2. रेस्पोंडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित
 3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पों.सं. 2 व 3

निर्णय

दिनांक 15.06.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 को पारिवारिक खर्च कर्ज अदायगी व वैध कार्यों मे रूपयो की आवश्यकता होने पर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट वादी को अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 77 रकबा 1.49 हैक्टेयर मौजा बोदियाना तहसील चित्तौड़गढ़ को विक्रय करना तय कर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट वादी को आराजी नम्बर 77 रकबा 1.49 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबे को मय हक हकुक बरख मेर पाली सहित 3 लाख रु. प्रति बीघा के हिसाब से विक्रय करना तय किया जिस पर अपीलान्ट वादी ने रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से उक्त आराजीयात क्रय कर 5 लाख रु. साईं पेटे रेस्पोंडेन्ट सं. 1 को अदा किया। जिस पर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट वादी के पक्ष मे विक्रय इकरार भी उक्त आराजीयात सम्पूर्ण को विक्रय करने एवं साईं पेटे राशि प्राप्त करने बाबत् निष्पादित कर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने अपनी निशानी अगूँठा कर गवाहान के हस्ताक्षर करा असल इकरारनामा अपीलान्ट वादी को सुपुर्द कर दिया। तथा विक्रय की गई आराजी का भौतिक कब्जा दिनांक 28.03.2003 को अपीलान्ट वादी को सुपुर्द कर दिया। तभी से


राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्त वादी क्रय की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 से अपीलान्त वादी ने कई बार रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा विक्रय की गई आराजीयात की रजिस्ट्री अपीलान्त वादी के पक्ष में कराने तथा शेष प्रतिफल राशि प्राप्त करने हेतु आग्रह किया किन्तु रेस्पोजेन्ट सं. 1 हर बार टलमटोल करती रही। वर्तमान में कृषि भूमियों की किमतों में बढ़ोतरी हो जाने से अब रेस्पोजेन्ट सं. 1 के मन में बदनियती आ गई। दिनांक 20.01.2013 को अपीलान्त वादी ने रेस्पोजेन्ट सं. 1 से पुनः उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री कराने एवं शेष प्रतिफल राशि लेने हेतु कहा। जिस पर रेस्पोजेन्ट सं. 1 ने अपीलान्त वादी के पक्ष में उनके द्वारा विक्रय की गई आराजीयात की रजिस्ट्री कराने व शेष प्रतिफल राशि लेने से इंकार कर दिया व धमकी दी की आराजीयात मेरे नाम है। वर्तमान में बाजार भाव से रुपये देते हो तो रजिस्ट्री करा दूंगी अन्यथा आराजीयात से तुम्हें जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लूंगी। तथा आराजीयात को दूसरे लोगों को विक्रय कर दूंगी। तभी से रेस्पोजेन्ट सं. 1 ने अपीलान्त वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करना शुरू कर दिया। उक्त आराजीयात को विक्रय करने हेतु प्रचार-प्रसार कर रही है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 कभी भी उक्त कृषि आराजीयात अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रहन विक्रय बक्षीस मुक्तकिल कर अपीलान्त को आराजीयात से बेदखल कर देगी। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी नोटिस की पालना में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में उपस्थित हुई। जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली में रेस्पोजेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। निवेदन किया कि वादिया का वादपत्र अपंजीकृत विक्रय इकरार दिनांक 28.03.2003 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त वादपत्र बाई बाय लॉ होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। विक्रय इकरार के आधार पर वादपत्र का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलान्त वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। न्यायहित में अपीलान्त वादी को सुना जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्त वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्त वादी ने इस न्यायालय में निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय में अपीलान्त वादी की ओर से निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। रेस्पोजेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
शिलीइगढ़ (रा.ब.)

सं. 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त वादी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलान्त की ओर से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्त वादी ने अपने वादपत्र में यह निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के खातेदारी की होकर रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने जरिये विक्रय इकरार दिनांक 28.03.2003 को अपीलान्त वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया तभी से अपीलान्त वादी जरिये विक्रय इकरार से उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी रेस्पोंडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया अपीलान्त वादी के कब्जे के काश्त में दखलदांजी कर उक्त आराजीयात को अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। अपीलान्त वादी का उक्त आराजीयात पर कब्जा होने से स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र में रेस्पोंडेन्ट सं. 1 की ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को दावा जवाबदावा विशेष कथन के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षों की साक्ष्य लिवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना साक्ष्य व सबूत के रेस्पोंडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी जिसका अपीलान्त वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। अपीलान्त वादी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में विशेष कथन के साथ निवेदन किया गया कि अपीलान्त वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान कराये जावे। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्त वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिनुसार बताते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विक्रय इकरार पर आधारित होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं था जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्त वादी का वादपत्र खारीज किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय व डिक्री विधिनुसार होकर अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्त वादी ने रेस्पोंडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा बोदियाना तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 77 जो रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में विक्रय इकरार दिनांक 28.03.2003 जो अपंजीकृत व प्रोपर स्टाम्प पर नहीं है, के आधार पर रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र का जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि विरुद्ध होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्त वादी का वादपत्र अपंजीकृत विक्रय इकरार के अधार पर होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। विक्रय इकरार के पालना सुनिश्चित करवाये जाने का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्त वादी की ओर से रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत वादपत्र जो कि विक्रय इकरार दिनांक 28.03.2003 जो रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपीलान्त वादी के पक्ष मे निष्पादित किया गया है। यदि रेस्पोंडेन्ट उसकी पालना करने मे असफल रहती है तो उसकी पालना करवाये जाने का वादपत्र सिविल न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस न्यायालय मे अपीलान्त वादी की ओर से जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमे भी अपील मेमो व बहस मे कही स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त कृषि आराजीयात का वादपत्र विक्रय इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्त वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्त वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 60/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2014 यथावत कायम रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटयी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)

अपील सं. 14/2014/डिक्री

श्री भैरूलाल पिंगा हीरा जाट निवासी बनाम
बोडिधाना नहसील व जिला चित्तौड़गढ़

- ① श्री सोहनो पुत्री उंगाराक आरि जाट
निवासी बोडिधाना हील बुकाम सोपुरा
नहसील उंगाराक जिला चित्तौड़गढ़
- ② उप-पंजीयत उपपंजीयन कार्यालय
चित्तौड़गढ़
- ③ भूमिधारी नहसील गार चित्तौड़गढ़
नहसील व जिला चित्तौड़गढ़



-अपीलान्त

-रेस्पोंडेंट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपरपठ अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दि. 17-02-2014

प्रकरण सं. 60/2013 अन्तर्गत धारा 188 रा. का. अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 15-06-2022 को अपीलान्त की ओर से

अधिवक्ता श्री जैराम परमार रेस्पोंडेंट की ओर से श्री सुरेश मल सम्पर्कार - राजकीय अभिभावक क्र. 2, 3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्त वादी अस्वीकार की जाकर अधिवक्ता विद्ववान् विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपरपठ अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 60/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17-2-2014 यथावत कायम रखी जाती है।

इस अपील के खर्च, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि रुपये हैं,
..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्च द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 15-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर किया है।

(श्री हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 15-06-2022

अपील खर्च : चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्त	रूपये	रेस्पोंडेंट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. रु. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. रु. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	